(v) STEPS FOR BETTER AVAILABILITY OF ENERGY IN RAJASTHAN

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : देश में ऊर्जा उत्पादन में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु राजस्थान प्रांत ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से दिनोदिन गिरावट की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान प्रांत में दो वर्षों से लगातार सूखे ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गांधी सागर बांध के निर्माण के बाद में सैकड़ों छोटे एवं बड़े बांध गांधी सागर के कैचमेंट एरिया में बनाकर गांधीसागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर में पानी के भराव में बड़ी रुकावट पैदा कर दी है, जिससे उपरोक्त वर्णित बांधों में बहुत कम पानी पहुंच पाता है, जिससे भी विद्युत उत्पादन को बड़ा धक्का पहुंचा है और दूसरी ओर सतपुड़ा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को पर्याप्त हिस्सा न देने के कारण भी स्थिति डांवाडोल हो गई है। उसके अतिरिक्त कोटा में दो अणु बिजली घर यांत्रिक त्रुटियों एवं मरम्मत की आवश्यकता बताकर एक वर्ष में करीब छः माह यदा-कदा बंद होने के कारण विद्युत उत्पादन को धक्का लगा है और अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है।

उक्त विद्युत संकट से राजस्थान प्रांत के उद्योगों को करोड़ों रुपयों की हानि हुई है जिससे सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों को बड़ा धक्का लगा है जिसके कारण कोई बाहर से और यहां का उद्यमी अपना धन उद्योगों में लगाने के लिए तैयार नहीं है। कृषि पर बड़ा आघात पहुंचा है।

केन्द्र सरकार उक्त भयंकर एवं जटिल स्थिति को देखते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश के विवाद को तुरंत हल करने में पहल करे, अणु बिजली घर के बार-बार बंद न होने के लिए ठोस स्थायी कदम उठावे और केन्द्र सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त थर्मल एवं अणु बिजली घर के निर्माण के लिए अधिक प्रावधान करे।

(vi) STEPS FOR BETTER AVAILABILITY OF FOODGRAINS IN FAIR PRICE SHOPS IN MADHYA PRADESH.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): मध्य प्रदेश के नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न के बढ़ते भावों तथा राशन की दुकानों से खाद्यान्न उपलब्ध न कराने के कारण गांव में रहने वाले मेहनतकश, खेतिहर मजदूर तथा कम आय के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

खाद्यान्न, शक्कर और सीमेंट के अपर्याप्त आवंटन के कारण स्थिति और अधिक गंभीर बन गई है।

राशन की दुकानों पर उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव है। खाद्य तेल के भाव काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति ग्रामीण पुनर्निर्माण के कामों के बंद हो जाने से अधिक चिन्ताजनक है।

अतएव केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश को खाद्यान्न, शक्कर और सीमेंट का पर्याप्त आवंटन कर नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न सहित सभी उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।